

मुख्यमंत्री भजनलाल के महत्वपूर्ण जल समझौतों से विकास की गंगा बहेगी- शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने बारां व झालावाड़ में 1258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

बारां/जयपुर, 17 अगस्त। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना समझौते से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, यमुना जल से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निरंतर विकास की गंगा बहेगी। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बारां, झालावाड़, कोटा के कृषि क्षेत्र में विकास का रोडमैप बनाया जाएगा। इससे किसान नई फसलों की पैदावार कर सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राजस्थान के लिए 3 हजार 473 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख 89 हजार 355 नवीन आवास निर्माण तथा कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नत योजना के लिए 340 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति के पत्र सौंपे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने,



केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

कृषि लागत कम करने और ऊर्इ आसान ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारां एवं झालावाड़ जिलों में 1 हजार 258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का

शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। पिछले ढाई साल में बारां के समग्र विकास के लिए 3 हजार 316 करोड़

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने व कृषि लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एवं झालावाड़ के लिए 6 हजार 474 करोड़ सहित कुल 10 हजार करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल पर बारां जिला प्रशासन की विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनों का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा, राधेश्याम बैरवा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

नितिन नबीन ... आईएसआई के शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के 255 संदिग्ध गिरफ्तार

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान के नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारियों के बाद प्रदेश की राजनीति में भी इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखा गया है, तो दूसरी ओर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर संगठन में उनका कद बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार है। ऐसे में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय संगठन में मौजूदगी आने वाले समय में केन्द्र और प्रदेश संगठन के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई नियुक्तियों से एक बात साफ है कि भाजपा ने राजस्थान के अनुभवी, संगठनात्मक और सामाजिक आधार वाले नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर प्रदेश को संगठन की नई रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब इन नियुक्तियों का असर राजस्थान भाजपा के भीतर आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों पर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों में 253 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

स्वतंत्रता दिवस के आसपास एसबीएन से जुड़ी संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने वाली प्रणाली

सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कार्यवाही कर आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम किये

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

समर्थित आतंकी समूह 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' को खत्म कर दिया और 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। शाह ने कहा कि आईएसआई से फंड पाने वाले इस समूह के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

कतर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी के साथ जरूरी पहचान संबंधी जानकारी देनी होगी। भारत में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने यूपीआई ऐप में विदेश से पन प्राप्त करने की सुविधा सक्रिय करनी होगी। इसके बाद भेजी गई राशि सीधे उसके यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाएगी। एक लेनदेन में न्यूनतम 10 कतर रियाल और अधिकतम 4,000 कतर रियाल भेजे जा सकेंगे। हालांकि, एक लेनदेन की अधिकतम भारतीय मुद्रा में सीमा एक लाख रुपये के बराबर होगी। प्रत्येक लेनदेन पर 15 कतर रियाल का सेवा शुल्क लिया जाएगा।

विधानसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के अनुरूप संचालित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सदी दल विधानसभा की गरिमा बनाए रखते हुए सत्र के सफल संचालन में सहयोग करेंगे।

शहजाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूनावाला ने भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से उन्हें लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिला।

उन्होंने कहा कि भाजपा और व्यापक संघ परिवार ने उन्हें जो अवसर और मंच प्रदान किया, उसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक युवा, पसमांदा मुस्लिम और गैर-वंशवादी व्यक्ति को भाजपा ने अवसर प्रदान किया। पूनावाला ने कहा कि वे उस पार्टी और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद को अलविदा कह रहे हैं, जिसे वे बेहद पसंद करते हैं।

“दिमागी नक्सल” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पारंपरिक राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर खुद को संघटित किया है।

स्वष्ट रूप से, मोदी का यह संदेश वामपंथी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज की आवाजों और सरकार के आलोचकों को निशाना बनाता है, जिन्हें भाजपा लंबे समय से “अर्बन नक्सल” कहती रही है।

इसमें असहमति, विशेषकर शासन, शिक्षा व्यवस्था की निफलताओं या हिंदुत्व की प्राथमिकताओं की आलोचना, को वैध राजनीतिक विरोध के बजाय माओवादी विद्रोह के वैचारिक विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

कांग्रेस ने इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस टिप्पणी को हताशा का पक्का संकेत बताया।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांग मानी, परीक्षा रद्द की

■ मुख्यमंत्री सोरेन की घोषणा पर आंदोलनरत छात्रों ने खुशी जताई, पर सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की

■ मुख्यमंत्री सोरेन ने लखनऊ की डेटा प्रोसेसिंग और परीक्षा करवाने वाली संस्था टीएसआर डेटा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व भर्तियों को रद्द करने की घोषणा की।

छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसले के लिए बधाई दी और इसे छात्रों के आंदोलन की बड़ी सफलता बताया।

हालांकि, आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मांगों मान ली गई हैं, लेकिन उनका आंदोलन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्रों ने कहा कि परीक्षाएं और भर्तियां रद्द करने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।

छात्रों की प्रमुख मांग अब पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर है। उनका कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच कराने पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षाएं रद्द करने से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी। दावाियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।

दूसरी तरफ, परीक्षा में सफल अर्थार्थियों ने मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है, "हम लोगों का क्या दोष है, जो हमारी परीक्षा रद्द कर दी गई?"

जेपीएससी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र से भी मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनके समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही थी।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम घोषित की

राममाधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त, पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बने

■ नई टीम में महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष तवज्जो दी गई है तथा संगठनात्मक अनुभव, युवा ऊर्जा व क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया गया है।

पुरंदरेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रती सिंह बादल, लाल सिंह अर्मा, एम. नागराज, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) होंगे। शिव प्रकाश और सौदान सिंह को फिर राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी दी गयी है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेन्द्र पटेल, हरिश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महासचिव होंगे। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने कुल 7 राज्यों से 8 महामंत्री बनाए हैं और सबसे ज्यादा दो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। चार महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

हेमांग जोशी को युवा मोर्चा, रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा, अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा, शिवेश कुमार राम को अनुसूचित जाति मोर्चा, मंगलाल रावत को अनुसूचित जनजाति और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान सौंपी गई है। अनिल बल्लू को फिर मीडिया संयोजक बनाया गया है। आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी, सिद्धार्थ यादव को सह संयोजक बनाया गया है। दीपक म्हरके को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट, अरुण यादव को सिंह, मुर्गाका देव बर्मन, रोहन गुप्ता,

राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, भोला सिंह, प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, संदीप पाठक, फांमोनो कोन्यक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, एम वेंकटेशन , राम मोधव, बैजयंत जय पांडा, डी

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अक्सर अपने आलोचकों को बदनाम करती है और बातें उन्हीं की मांगों को अपना लेती है। उन्होंने इसके उदाहरण के रूप में जातीय जनगणना का हवाला दिया।

विपक्ष के अन्य नेताओं, जिनमें भाकपा के डी. राजा भी शामिल हैं, ने इस शब्द को असहमति को दर्शाते कर्त्ताकृत करने और सरकार को सवाल उठाने वालों को डराने की कोशिश बताया है।

‘अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनावई के दौरान याचिकाकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने आरोप लगाया कि एयरलाईस जिस तरह से यात्रियों से शुल्क वसूल रही हैं, उसके लिए बनाए गए आधिकारिक नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है।

पारदर्शी मानदंड और कड़े डंड का प्रावधान हो।

विज्ञापन एजेंसियों और सेलिब्रिटीज से भी यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे प्रतिबंधित वस्तुओं की ब्रांड पहचान वाले उत्पादों का विज्ञापन करने से पहले पूरी जाँच-पड़ताल करें। इस तरह, महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेजे गए नोटिस सिर्फ एक और सेलिब्रिटी विवाद बनकर न रह जाएं। वे एक ऐसे सवाल को सुझावें का मौका दे सकते हैं जो बरसों से बना हुआ है: कोई उत्पाद कानूनी हो सकता है, लेकिन क्या उसका विज्ञापन कानूनी तौर पर किसी ऐसी चीज के विज्ञापन के रूप में काम कर सकता है, जो खुद कानूनी नहीं है?

जब तक इस सवाल का जवाब एक स्पष्ट रेगुलेटरी टेस्ट के ज़रिए नहीं दिया जाता, तब तक सरोटेट विज्ञापन की यह कानूनी खामी प्रतिबंधित ब्रांडों को बाज़ार में अपनी पहचान बनाए रखने का मौका देती रहेगी और उन्हें अपने उत्पाद को खुलेपन विज्ञापन करने की जरूरत भी पड़ेगी।

दिखाई दें, वहाँ विज्ञापन देने वाले पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ब्रांड विस्तार वास्तव में एक वास्तविक और स्वतंत्र कारोबार है। सेलिब्रिटी के विज्ञापन में शामिल होने की भी विशेष रूप से जाँच होनी चाहिए। कोई एक्टर यह तर्क दे सकता है कि उसने इलायची का विज्ञापन किया, तंबाकू का नहीं। लेकिन अगर विज्ञापन का मुख्य मकसद प्रतिबंधित तंबाकू ब्रांड की पहचान को लाखों उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है, तो इस अंतर को सही ठहराना लगातार मुश्किल हो जाता है।

उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वैध कारोबारों को कानूनी उत्पादों का विज्ञापन करने से रोका जाए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि किसी कानूनी उत्पाद को गैर-कानूनी उत्पाद के विज्ञापन के लिए सुविधाजनक माध्यम बनने से रोका जाए।

इसलिए भारत को ब्रांड विस्तार के लिए एक अधिक स्पष्ट और तकनीक से स्वतंत्र नियम की जरूरत है, जिसमें